

श्री जयराम रमेश : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर कोई उदाहरण है तो मुझे दीजिए, मैं इस संबंध में जरूर कार्यवाही करूंगा।

Illegal mining of coal

*225.SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:††

SHRI N.K. SINGH:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government has decided to constitute a high level surveillance wing, involving the police, CISF and other intelligence departments, to check the rampant illegal coal mining in certain districts of West Bengal and Jharkhand;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether, due to indiscriminate illegal mining, Government is losing crores of rupees every year; and

(d) if so, to what extent the surveillance wing would curb the practice of illegal coal mining?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No such decision has been taken by the Government to initiate joint action for the prevention of illegal mining. However, Task Forces have been constituted by the State Governments of Jharkhand and West Bengal, at the State and District level. Since law and order is a State subject, primarily it is the responsibility of State/District administration to take necessary deterrent action to stop/curb illegal mining. Coal India Limited and its subsidiaries are also associated closely with the concerned State and District authorities to deal with this menace.

(c) Illegal mining mostly takes place in old and abandoned mines, small and isolated patches, areas situated at remote/isolated places from mines, which are scattered over a large area, exposed coal seams and also in areas not in the leasehold areas of public sector coal companies. Due to clandestine nature of illegal mining activities, the exact quantum of coal, so mined and losses incurred on account of illegal mining cannot be ascertained. However, on the basis of raids conducted by the security personnel of coal companies as well as joint raids with the law and order authorities of the concerned State Government, the approximate quantity of coal recovered during 2008-09 and its value thereof were approximately 8,584 tonnes and Rs.1.02 crore respectively.

(d) Does not arise in view of the answer given to parts (a) & (b) above.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, I would like to inform the hon. Minister that in 2006, his predecessor had set up a High Level Committee to go into the issue to try and curb illegal mining, and, more recently, XLRI, Jamshedpur as well as the Indian School of Mines, at the behest of the

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri D. Raja

Government of Jharkhand, has conducted a study to assess where the mines are, what is the amount of coal and whether the coal is low-lying, whether it can be run on a cooperative basis. Sir, I would like to ask the Minister what are the major recommendations of both these Committees and what does the Government propose doing on the basis of these recommendations.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न को पूछा है और जिस तरह से पूछा है, मैं इनकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरीके से इन क्षेत्रों में कोयले की चोरी हो रही है, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि कैसे इस चोरी को रोका जा सकता है, ऐसी कौन सी स्टडी कराई गई है। हमारे मंत्रालय ने इसके पहले Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur से स्टडी कराई थी। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम पढ़ दें। **...(व्यवधान)...** इसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री की जो Indian School of Mines हैं, उनसे भी स्टडी कराई गई है। उन्होंने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो चोरी इन क्षेत्रों में हो रही है, पिलफ्रेज हो रही है, इल्लीगल माइनिंग हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इन क्षेत्रों की गरीबी है, इन क्षेत्रों का पिछड़ापन और दूसरा कारण, इन क्षेत्रों में जिस ढंग से स्टेट गवर्नमेंट को इन चोरी को रोकने के लिए एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि **...(व्यवधान)...** आप अच्छी तरह जानते हैं कि **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. **...(Interruptions)...** We are running short of time, let the question be answered. **...(Interruptions)...**

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस यह स्टेट सब्जेक्ट है। जितनी हमारी माइंस में चोरी होती है, उनको रोकने की हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी माइन्स के अलावा जो कोल प्रोपर्टीज में चोरी हो रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट पुलिस की है और लॉ एंड ऑर्डर की है। हम स्टेट गवर्नमेंट से बराबर मिलते रहते हैं, अभी हमने जब से यह कार्यभार संभाला है, मैं जिन स्टेट्स में गया हूँ उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स से मिला हूँ। झारखंड के गवर्नर से मिला, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया, हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि सरकार की नाक के नीचे इतनी जबर्दस्त चोरी हो रही है, इसके बाद भी अगर सरकार कड़े कदम नहीं उठाती है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें आश्वासन मिला है, झारखंड के गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हम एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठाएंगे, जिसके माध्यम से कोयले के अवैध खनन में और कोयले की चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हम माननीया सदस्या को आश्वासन करते हैं कि जिस तरीके से हमने शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस चोरी पर कुछ न कुछ अंकुश जरूर लगेगा। हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि हम चोरी रोक लेंगे, न हम यह कह सकते हैं कि इल्लीगल माइनिंग हम रोक लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आप बैठ जाइए **...(व्यवधान)...** आप बैठ जाइए। Please do not interrupt **...(Interruptions)...**

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, इस पर कुछ न कुछ अंकुश जरूर लगेगा, यह आश्वासन हम जरूर देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Let us not waste any time, please resume your places. **...(Interruptions)...**

SHRI PARIMAL NATHWANI: Sir, I want to say...

MR. CHAIRMAN: The second supplementary now. ...*(Interruptions)*... Please do not interrupt, the floor has not been given to you. Please resume your place. If you wish to ask a question, there is a procedure for it.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: The hon. Minister says that it is a State-subject but he would understand more than anyone else since he was in the Home Ministry in the previous tenure that it is the law and order subject as well. Therefore, would the Centre consider setting up some sort of a formal mechanism by which it becomes mandatory that the Centre and the States jointly start reviewing the progress made? This is going on for very long and to simply palm it off as the State-subject is not going to take us any further. So, would he set up a joint mechanism to jointly coordinate and take steps to prevent the illegal mining?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, हमारे प्रश्न का जवाब खुद ही इन्होंने दे दिया है कि यह लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन जैसा कि माननीया सदस्य ने पूछा है, हम खुद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में वहाँ के मुखिया से मिलकर, वहाँ के मुख्य मंत्री से मिलकर और अगर वहा गवर्नर है तो उनसे मिलकर हम कैसे इस क्षेत्र में चोरी को रोक सकते हैं, इस क्षेत्र में कैसे इल्लिगल माइनिंग को रोक सकते हैं, यह प्रयास कर रहे हैं। इसके सकारात्मक प्रयास माननीया सदस्य को बहुत जल्दी दिखलाई पड़ेंगे।

SHRI N.K. SINGH: Sir, arising out of the Minister's reply to the first part to the first supplementary asked by the hon. Member, would the Minister concede that the basic cause which encourages illegal mining is the high profitability arising out of an over-regulated regime, which exists in the coal sector? Would the Minister, while considering detailed action of coordination between States, look to a kind of a regulatory framework which mitigates illegal mining, encourages productivity, and enhances overall availability of coal for the energy sector?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें कोई शक नहीं है कि कोयले की चोरी उस क्षेत्र में उद्योग बन गया है। हजारों की तादाद में लोग इसको रोजगार का साधन बना चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यह सब कुछ गरीबी के कारण, पिछड़ेपन के कारण, अशिक्षा के कारण हुआ है। ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती वृंदा कारत : मंत्री जी, उनका सवाल है कि आप illegal को legal बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : प्लीज ...*(व्यवधान)*... आप लोग बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... आप लोग बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...
Please stop this. ...*(Interruptions)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, अगर माननीय सदस्य का सवाल है कि illegal को हम legal बनाएंगे, तो illegal को legal कोई नहीं बना सकता है। ...*(व्यवधान)*... माननीय सभापति जी, illegal को legal कोई नहीं बना सकता है। ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... प्लीज, आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... Please resume your place.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति जी, illegal को legal कोई नहीं बना सकता है, लेकिन कुछ pragmatic कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। जैसे - जिन क्षेत्रों में ज्यादा चोरी होती है, वहाँ पर कोआपरेटिव

सोसायटी बनाकर स्टेट गवर्नमेंट्स छोटी-छोटी coal प्रोपर्टी उनको दे दें और उनसे यह कहें कि वह कोआपरेटिव सोसायटीज बनाकर, उसमें वहां के किसानों को, गरीबों को भागीदार बनाकर, उन सोसायटीज के माध्यम से माइनिंग कराएं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. ...*(Interruptions)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जिससे कि उनको रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो जाए और वास्तव में चोरी भी रुक जाए। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी, उसका कारण है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी इन्चाल्व है। अगर कोआपरेटिव सोसायटीज को माइनिंग करने के लिए दिया जाता है और उन किसानों से कहा जाता है कि आप लोग माइनिंग करिए। उन लोगों के पास न तो ऐसे उपकरण हैं, न ही उनके पास कोई ऐसी जानकारी है, न ही उनके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग है। अगर माइनिंग करते समय कोई हादसा हो जाता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं सरकार पर आती है। हम लोग प्रयास यह कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाएं और illegal माइनिंग पर अंकुश लग सके।

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... I am on the question of propriety. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There is no point of order in the Question Hour. ...*(Interruptions)*... What is the point?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, there is an insinuation that is being made by the Minister and that is गरीबी कारण है चोरी का सर, यह कहना कि गरीब ही चोरी करता है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... If that is so, I will look into it.*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I want to submit जहां तक पता है अमीर लोग ही ज्यादा चोरी करते हैं। इस तरह से गरीबों का अपमान कर रहे हैं।... सर, मंत्री जी, इस सदन में गरीबों का अपमान नहीं करें। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने गरीबों का अपमान किया है। इसके लिए मंत्री जी माफी मांगें। मंत्री जी ये शब्द वापस लें। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय सभापति जी, माननीय येचुरी जी ने हमारी भावनाओं को और हमारे भाव को सही तरीके से नहीं समझा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, आप वहां से ऐसा नहीं करेंगे। आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आपने अगर यह अर्थ निकाला है कि गरीबी ही चोरी का कारण है, तो यह बिल्कुल अनुचित अर्थ है। ...**(व्यवधान)**... मेरे कहने का आशय यह है कि जो illegal माइनिंग जो हो रही है, उसके पीछे उस क्षेत्र के पिछड़ेपन का, उस क्षेत्र की गरीबी का, उस क्षेत्र की बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। मेरे कहने का आशय यह है कि ...**(व्यवधान)**... इसमें अगर आप यह समझते हैं कि मैं यह कह रहा हूँ कि ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर : पूरा देश जानता है कि कोयला चोरी होता है और इसमें माफिया शामिल होता है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: If you wish me to conclude the Question Hour, I will do so. ...*(Interruptions)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ...*(व्यवधान)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I wish to submit something. ...*(Interruptions)*... Please allow me, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is that you wish to raise? ...*(Interruptions)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : देखिए, आप बैठ जाइए! ...*(व्यवधान)*... पाणि जी, आप बैठ जाइए! ...*(व्यवधान)*... देखिए, आप बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं! ...*(व्यवधान)*... आप ऐसा मत कीजिए! आप बैठ जाइए! ...*(व्यवधान)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ?

श्री सभापति : इनको सवाल पूछने दीजिए, तब जवाब दीजिए! ...*(व्यवधान)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, जो सवाल सीताराम येचुरी जी ने उठाया है! ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : वह सप्लीमेंट्री सवाल नहीं है ...*(व्यवधान)*...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, इस क्षेत्र में बड़े-बड़े माफिया सक्रिय हैं, इस बात को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ! ...*(व्यवधान)*... उन माफियाओं के उकसाने पर ही ...*(व्यवधान)*... मैं जवाब दे रहा हूँ! ...*(व्यवधान)*... इन माफियाओं के उकसाने से ही वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है। उन माफियाओं से निपटने का काम हमको भी करना पड़ेगा और राज्य सरकारों को भी करना पड़ेगा! ...*(व्यवधान)*...

श्री बलबीर पुंज : सर, उन्होंने पहले कहा कि गरीबी चोरी का कारण है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए! ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: You are not allowing me to ...*(Interruptions)*... मैं क्या करूँ? ...*(व्यवधान)*... आप बैठ जाइए! आप बैठ जाइए! ...*(व्यवधान)*... मंत्री जी, आप बैठ जाइए! प्लीज! ...*(व्यवधान)*...

श्री बलबीर पुंज : पहले कहा कि गरीब लोग चोरी करते हैं और बाद में कहा कि माफिया करते हैं! मंत्री जी को पहले बयान पर माफी मांगनी चाहिए! ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, प्लीज! ...*(व्यवधान)*... Stop interrupting please. बलबीर जी, आप बैठ जाइए, प्लीज! ...*(व्यवधान)*... प्लीज! ...*(व्यवधान)*... देखिए, पाणि जी, ...*(व्यवधान)*... I am afraid. ...*(Interruptions)*... Just one minute please. ...*(Interruptions)*... The Chair is now making a note. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY : Sir, can I now...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए! ...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार : क्या आप इनके उत्तर से सहमत हैं? एक तरफ गरीब को ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : देखिए! ...*(व्यवधान)*... अगर उनके जवाब से आपको कोई एतराज है, तो आप अलग से पूछिए!

श्री विनय कटियार : सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ! ...*(व्यवधान)*... मंत्री जी! ...*(व्यवधान)*...

एक माननीय सदस्य : वे क्षमा मांगें! ...*(व्यवधान)*...

श्री शिवानन्द तिवारी : अगर मंत्री जी ने गरीबों का अपमान किया है, ...*(व्यवधान)*... इनको खेद व्यक्त करना चाहिए! ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN : I can't hear anything.

DR. K. MALAISAMY: Okay, let me finish my chance. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : देखिए, आप अपने साथी का हक मार रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। सदन में गरीबों को ...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : आप ज़रा बैठ तो जाइए, भाई। ...*(व्यवधान)*... बलबीर जी, प्लीज़। पाणि जी, प्लीज़। ...*(व्यवधान)*... प्लीज़। ...*(व्यवधान)*...

DR. K. MALAISAMY: Mr. Chairman, Sir, you have given the chance to me. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one minute please, देखिए, टाइम जाया हो रहा है। ...*(व्यवधान)*... The Chair is getting the impression that there is a concerted effort to disrupt the Question Hour and not allow the questions to be answered. If that is so, I will conclude the Question Hour. ...*(Interruptions)*... Please put your question. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Should I not get a chance? Everybody is interfering when my chance is given.

श्री विनय कटियार : आपका chance है, हम आपके chance को नहीं खोने देंगे। ...*(व्यवधान)*...

DR. K. MALAISAMY: You wait. You speak when your chance is given. I should be given the permission. I should be allowed to speak. *

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, अभी तक इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Well, he will translate it for you.

DR. K. MALAISAMY: It is not possible for him to answer? Can he answer? I am trying to put my question in Tamil. Can he afford to speak in Tamil?

MR. CHAIRMAN: You did not give a notice. Please put your question in either Hindi or English,

DR. K. MALAISAMY: *

MR. CHAIRMAN: Please Dr. Malaisamy, no notice has been given.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, चूंकि ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं इनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*...

DR. K. MALAISAMY: If he cannot understand Tamil I am capable of speaking in English also.

MR. CHAIRMAN: Please do. You have taken too much time.

DR. K. MALAISAMY: As far as illegal mining is concerned, my information is, that this is being done with the active connivance and consent of your lower level officers. If that be the case, do you have any mechanism to control and contain that kind of malpractices?

* Hon. Member spoke in Tamil.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां कहीं भी चोरी होती है, जहां कहीं भी illegal mining होती है, जहां कहीं भी कोई गलत कार्य होता है, उसमें कहीं न कहीं अधिकारी व वहां के लोगों की मिलीभगत होती है। इसलिए मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: The Minister knows English. When the question is in English, he should reply in English. Why does he not reply in English?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैं यह प्रयास करूंगा ...**(व्यवधान)**... सर, मैं यह प्रयास करूंगा कि संबंधित अधिकारियों से मिलकर और अपने कोयले अधिकारियों के साथ मिलकर, इस चोरी को रोका जाए।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Clearance to new channels

*222. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- whether it is a fact that Government has granted clearance to a number of new channels;
- if so, the details thereof;
- whether it is a fact that several existing channels have reduced their staff; and
- if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) and (b) Approval of channels is a continuing process. As part of this process, 23 TV channels have been approved to uplink from India/downlink in India as per uplinking and downlinking guidelines during the month of June, 2009. The details are given in the Statement (*See below*).

(c) and (d) Government does not maintain information about the staff of Private channels.

Statement

Details of channels permitted to uplink/downlink from India

Sl.No.	Name of the Channels	Name of the Companies	Date of Approval	Date of Permission
1	2	3	4	5
1.	Kanak Sambad	Eastern Media Ltd.	19.6.2009	23.6.2009
2.	Kalaighar Asia	Kalaighar Tv Pvt. Ltd.	26.6.2009	30.6.2009
3.	ABN-Andhra Jyothy	Aamoda Broadcasting Co. Ltd.	26.6.2009	30.6.2009